

[2023] 5 एस. सी. आर. 410

/

[2023] 5 एस सी आर।

/

प्रवर्तन निदेशक v.

आदित्य त्रिपथी

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 1401) 12 मई, 2023

/

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, न्यायाधीशगण]

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002: धारा 45-जमानत पर विस्तार-बोलियों को कम करने के आरोप की स्थिरता-अभियुक्त ने यू/एस. एस. पर आरोप पत्र दायर किया। 120-बी, 420, 468, 471 भारतीय दंड संहिता सी. और एस. 7 आरडब्ल्यू एस. 13(2) पी. सी. अधिनियम के अंतर्गत , अनुसूचित अपराध-पी. एम. एल. अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपराध बाद में जोड़े गए-प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन की जांच शुरू की-प्रतिवादी नं. 1 गिरफ्तार-इसके बाद, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत पर बढ़ा दिया-स्थिरता-आयोजित:पोषणीय नहीं-उच्च न्यायालय ने एस की कठोरता पर विचार नहीं किया। 45 न ही पी. एम. एल. ए. अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के लिए अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता पर विचार किया गया और न ही पी. एम. एल. ए. अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अभी भी चल रही है-केवल इसलिए कि अन्य अभियुक्तों को बरी/आरोपमुक्त कर दिया गया है, यह प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ जांच जारी नहीं रखने का आधार नहीं हो सकता है-केवल इसलिए कि, पूर्वनिर्धारित अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया जा सकता है, यह पी. एम. एल. अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के संबंध में अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है-पूर्वनिर्धारित अपराधों की जांच और पी. एम. एल. अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अलग और विशिष्ट हैं-मामले जमानत आवेदनों पर नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजे गए हैं। 120-बी, 420, 468 और 471-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 -एस. 7 आरडब्ल्यू एस. 13(2).

/

/

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 1401।

/

2021 के सी. आर. एल. पी. संख्या 1146 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 02.03.2021 के निर्णय और आदेश से।सह

आपराधिक अपील सं।1402 2023 तक।

/

410

411

प्रवर्तन निदेशक बनाम आदित्य त्रिपाठी ए

/

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मारोरिया, मुकुल सिंह, एस. ए. हसीब, श्रीमती दीपावली दत्ता, राजन कुमार चौरसिया, जोहेब हुसैन, कन्नू अग्रवाल, शरत नांबियार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।राकेश खन्ना, अमन लेखी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, संतोष कुमार त्रिपाठी, सिद्धार्थ कृष्ण द्विवेदी, वरुण के चोपड़ा, युगांत शर्मा, आयुष जिंदल, तुषार गुप्ता, रोहिन ओझा, मैसर्स वी. के. सी. विधि ऑफिस, एड.प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 1146/2021 और 1147/2021 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं) से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त जमानत आवेदनों को अनुज्ञात है और प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद द्वारा एफ. नं. में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (इसके बाद पीएमएल अधिनियम, 2002 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत अपराधों के संबंध में संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत पर बढ़ाने का निर्देश दिया है। ई. सी. आई. आर./एच. वाई. जेड. ओ./36/2020 महानगर सत्र न्यायाधीश, हैदराबाद की फाइल पर प्रवर्तन निदेशालय ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

/

/

2. कि आर्थिक अपराध शाखा, भोपाल द्वारा एक प्राथमिकी संख्या 10.04.2019 दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 468 और 471, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 7 (सी) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए लगभग 20 व्यक्तियों/कंपनियों को आरोपी के रूप में नामित किया गया था। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि ई-निविदा संख्या 91,93 और कुल कार्यों के लिए 94 करोड़ रुपये की राशि है। मेसर्स जी. वी. पी. आर. इंजीनियर्स लिमिटेड, मेसर्स द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड और मेसर्स आई. एम. सी. (एस. आई. सी.) प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड को सबसे कम बोली लगाने वाला बनाने के लिए मध्य प्रदेश जल निगम की ₹1 करोड़ की बोली में बदलाव किया गया। एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद, आर्थिक अपराध शाखा, भोपाल ने जाँच की और 04.07.2019 पर सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। आरोप-पत्र के अध्ययन पर, यह पाया गया कि अभियुक्तों ने पीएमएल अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भी अपराध किए हैं क्योंकि जिन अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया था, अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 468 और 471 और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 7 भी अनुसूचित अपराध हैं और इसलिए प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद ने यह आदेश दिया है।

/

/

/

/

412

/

[2023] 5 एस सी आर।

एफ. नं. में धन शोधन की जांच शुरू की। ईसीआईआर/हाइजो/36/2020। कि संबंधित प्रत्यर्थी संख्या 1 को संबंधित अपीलों में 19.01.2021 पर गिरफ्तार किया गया था, इसलिए, उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही उपरोक्त जांच/मामले के संबंध में उन्हें जमानत पर बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान जमानत आवेदन दायर किए। आक्षेपित आदेशों द्वारा, उच्च न्यायालय ने जमानत पर संबंधित अपीलों में प्रतिवादी संख्या 1 को बढ़ाने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद द्वारा जाँच किए जा रहे मामले में जमानत पर संबंधित

अपीलों में प्रत्यर्थी संख्या 1 का विस्तार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश वर्तमान अपीलों के विषय हैं।

/

/

3. श्री के. एम. नटराज, विद्वान ए. एस. जी., अपीलार्थी की ओर से पेश हुए-प्रवर्तन निदेशालय और श्री राकेश खन्ना और श्री अमन लेखी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश हुए।

3.1 प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए विद्वान ए. एस. जी. श्री नटराज ने कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त को जमानत पर बढ़ाने में गंभीर गलती की है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित प्रतिवादी संख्या 1-अभियुक्त को जमानत पर बढ़ाते हुए उच्च न्यायालय ने पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 45 की उचित रूप से सराहना नहीं की है।

/

/

3.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पी. एम. एल. अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों की गंभीरता की उचित रूप से सराहना और/या विचार नहीं किया है।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 को केवल इस आधार पर जमानत पर बढ़ा दिया है कि जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अभी भी चल रही है और इसलिए, यह कहना गलत है कि जांच पूरी हो गई है। 4. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को जमानत पर बढ़ाने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की है। 4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में जहां तक आक्षेपित एफ. आई. आर. का संबंध है, अर्थात् पूर्वनिर्धारित अपराधों के लिए अन्य अभियुक्तों को बरी/आरोपमुक्त कर दिया गया है।

/

/

/

प्रवर्तन निदेशक बनाम आदित्य त्रिपाठी [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि जांच समाप्त हो गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है, उच्च न्यायालय ने आरोपी-संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत पर उचित रूप से बढ़ा दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आरोपी मार्च, 2021 से जमानत पर हैं, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। 5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान वकील को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

/

6. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित प्रतिवादी संख्या 1-आरोपी अनुसूचित अपराधों के लिए और उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय पीएमएल अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत धन शोधन के अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच का सामना कर रहे हैं। एफ. आई. आर. नं. 12/2019 के संबंध में अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभी भी जांच/जांच चल रही है। एक बार जब संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ पीएमएल अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपराधों के लिए जांच/जांच चल रही है, तो पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता पर विचार करने की आवश्यकता है। पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 45 इस प्रकार है:-

/

/

“45. संज्ञेय और गैर-जमानती होने वाले अपराध।—

(1) [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, [इस अधिनियम के तहत] अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

/

((i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और

((ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है:

/

बशर्ते कि एक व्यक्ति, जो सोलह वर्ष से अंतर्गत आयु का है, या एक महिला है, या बीमार है या अंतर्गत जोर है [या अपने दम पर या एक करोड़ रुपये से अंतर्गत की राशि के धन शोधन के अन्य सह-अभियुक्तों के साथ आरोपी है], को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निर्देश देता है:

/

बशर्ते कि विशेष न्यायालय धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके कि -

/

414

/

[2023] 5 एस सी आर।

((i) निदेशक; या

((ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में उस सरकार द्वारा बनाए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो।

/

[(1-क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध की जांच तब तक नहीं करेगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विशेष रूप से अधिकृत नहीं किया जाता है, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित की जाएं।

/

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत देने पर उस समय लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत सीमाओं के अलावा है। "

/

आक्षेपित निर्णयों और आदेशों द्वारा और जमानत देते समय, उच्च न्यायालय ने पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता पर विचार नहीं किया है।

6.1 अन्यथा, उच्च न्यायालय ने धन शोधन के कथित अपराधों और पीएमएल अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपराधों के आरोपों की प्रकृति और गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, यह कहा जा सकता है कि ये धन शोधन के बहुत गंभीर आरोप हैं जिनकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

/

6.2 अब जहाँ तक संबंधित प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुतियाँ हैं कि संबंधित प्रत्यर्थी संख्या 1 का नाम अनुसूचित अपराधों के संबंध में एफ. आई. आर. में नहीं था और/या जहाँ तक पूर्वनिर्धारित अपराधों का संबंध है, अन्य सभी अभियुक्तों को बरी/बरी कर दिया गया है, केवल इसलिए कि अन्य अभियुक्तों को बरी/बरी कर दिया गया है, यह संबंधित प्रत्यर्थी संख्या 1 के संबंध में जांच जारी नहीं रखने का आधार नहीं हो सकता है। निर्धारित अपराधों के संबंध में संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ जांच चल रही है। इसलिए, इस स्तर पर अनुसूचित अपराधों के लिए जांच/जांच ही पर्याप्त है।

/

/

6.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के साथ जो विचार किया जाता है वह यह है कि

/

415

प्रवर्तन निदेशक बनाम आदित्य त्रिपाठी [एम. आर. शाह, जे.]

संबंधित प्रतिवादी नंबर 1-अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और इसलिए, जांच पूरी हो गई है। हालांकि, उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने और सराहना करने में विफल रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएल अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के संबंध में जांच अभी भी चल रही है। केवल इसलिए कि पूर्वनिर्धारित अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया हो सकता है, यह पीएमएल अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के संबंध में आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है। पूर्वनिर्धारित अपराधों की जाँच और पी. एम. एल. अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जाँच अलग और विशिष्ट हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक विचार को ध्यान में रखा है। पी. एम. एल. अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अभी तक जारी है।

/

/

7. जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने न तो पी. एम. एल. अधिनियम, 2002 की धारा 45 की कठोरता पर विचार किया है और न ही पी. एम. एल. अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के लिए अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता पर विचार किया है और उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि पी. एम. एल. अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अभी भी चल रही है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत पर बढ़ाने के लिए पारित किए गए आक्षेपित आदेश अस्थिर हैं और मामलों को यहां ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद जमानत आवेदनों पर नए सिरे से निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाना आवश्यक है।

/

/

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, ये दोनों अपीलें सफल होती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक याचिका संख्या 1146/2021 और 1147/2021 में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश-संबंधित प्रतिवादी संख्या 1-जमानत पर संबंधित अपीलों में अभियुक्त को एतद्द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है। उस संबंधित प्रत्यर्थी संख्या 1 को अब आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम न्यायालय या संबंधित जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में और संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 के ऊपर दिए गए आदेश के अनुसार एक सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने के बाद जमानत आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है। वर्तमान अपीलों को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक अनुज्ञात जाती है।

/

/

निधि जैन

अपीलों की अनुज्ञात गई।

/

(सहायक: अभिषेक प्रताप सिंह और मयंक बत्रा, एलसीआरए)